RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 09 OCTOBER TO 15 OCTOBER 2019 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 7 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

प्रमुख बंदरगाहों पर माल ढुलाई मामूली बढ़कर 34.8 करोड़ टन
Page 3

ग्रॉसरी स्टोर्स को भी मिल सकती है खांसी और जुकाम की दवा बेचने की मंजूरी
Page 4

जल्द बिना हॉलमार्क के गहने बिकना होंगे बंद, प्रस्ताव मंजूर
Page 7

editoria!

रिजर्व बैंक का संकेत

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते रेपो रेट में लगातार पांचवीं बार कटौती करते हुए उसे 5.15 फीसदी पर ला दिया, जो पिछले 9 वर्षों में सबसे कम है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक देश के सभी व्यापारिक बैंकों को लोन देता है। खास बात यह है कि पिछली कटौतियों का ज्यादातर फायदा बैंकों तक ही रह गया था, लेकिन अभी कई बैंकों का उधारी रेट रेपो रेट से जुड़ जाने से यह आम ग्राहकों तक पहुंच सकता है। बाजार में सस्ता कर्ज पहुंचने की गुंजाइश पर शेयर बाजार को उत्साहित होना चाहिए था लेकिन हुआ उलटा। रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद शेयर बाजार में अच्छी-खासी गिरावट दिखी। इसकी वजह रही ब्याज दर में कटौती के साथ ही जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान में की गई कतरब्योंत। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.9 फीसदी से घटा कर 6.1 फीसदी कर दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि 6.5 फीसदी तक की सालाना विकास दर हासिल कर लेना अब भी मुमकिन है जबकि सरकार सात फीसदी का लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रही है। लेकिन इन दावों से हटकर देखें तो हालात मुश्किल ही दिखते हैं। ढहती ग्रोथ रेट को संभालने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि सरकार अब भी समस्या पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रही। उसका प्रयास इसको कम करके पेश करने, आंकड़ों को ऐसे नहीं वैसे दिखाने, और जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनसे सब कुछ ठीक हो जाने के दावे करने तक ही सीमित नजर आता है। रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती के ताजा कदम को ही देखें तो इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन विकास की अटकी हुई गाड़ी इसी के दम पर सरपट दौड़ पड़ने की उम्मीद बेजा ही कही जाएगी। ब्याज दरों में लगातार कटौती के बावजूद जब बाजार में कर्ज उठाने की रफ्तार ही इतनी मरी-गिरी है तो फिर कटौती की एक और किस्त से भला कौन सा चमत्कार हो जाएगा? जानकारों के मुताबिक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या मांग में कमी की है। जब तक सरकार इस मुश्किल से निपटने के बहुत सारे उपायों पर एक साथ काम नहीं शुरू करती तब तक कॉरपोरेट कंपनियों को करों में छूट, सस्ता कर्ज और आयकर में प्रस्तावित कटौती हाशिये की हलचल ही बने रहेंगे। एक्सपोर्ट का माहौल तो जल्दी सुधरने वाला है नहीं, ऐसे में कंपनियां अपना उत्पादन तभी बढ़ाएंगी जब उन्हें घरेलू बाजार में अपने माल के खरीदार नजर आएंगे। इस लिहाज से दीर्घकालिक रणनीति किसानों की आमदनी और कम पगार वाली नौकरियों की तादाद बढ़ाने की ही हो सकती है। तात्कालिक कदमों की बात करें तो लगभग तैयार खड़ी हाउसिंग परियोजनाओं और छोटे-छोटे गैप्स की वजह से लंबित पड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करके उन्हें उत्पादक स्थितियों में लाना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

आर्थिक मंदी के बीच जीएसटी कलेक्शन में 19 महीने के दौरान सबसे बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। एजेंसी

जीएसटी कलेक्शन में अगस्त महीने की तुलना में सितंबर में करीब छह हजार करोड़ से ज्यादा की गिरावट आई है। अगस्टी में जीएसटी कलेक्शन की राशि 98,202 करोड़ रूपये थी जो सितंबर महीने में घटकर 91,916 करोड़ रूपये हो गयी।

वस्तु एवं सेवा कर (उएऊ) का संग्रह सितंबर 2019 में 2.67 प्रतिशत गिरकर 91916 करोड़ रुपये पर आ गया जो पिछले वर्ष इसी महीने में संग्रहित 94442 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 2.67 प्रतिशत कम है। ये कलेक्शन बीते 19 महीनों में सबसे कम रहा।

इस वर्ष अप्रैल, मई और जुलाई में यह राशि एक-एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रही थी। जून में यह लगभग एक लाख करोड़ रुपये रहा था। अगस्त में यह राशि 98202 करोड़ रुपये रही थी।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि सितंबर में संग्रहित जीएसटी में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 16630 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी संग्रह 22598 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी संग्रह 45069 करोड़ रुपये और उपकर संग्रह 7620 करोड़ रुपये रहा। एकीकृत जीएसटी में 22097 करोड़ रुपये और उपकर में 728 करोड़ रुपये आयात से प्राप्त हुये हैं। अगस्त महीने के 30 सितंबर तक 75 लाख 94 हजार जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरे गये। सरकार ने एकीकृत जीएसटी से 21131 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी और 15121 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी के खाते में हस्तांतरित किया है। नियमित आवंटन के बाद जून में केन्द्र सरकार का कुल जीएसटी राजस्व 37761 करोड़ रुपये और राज्यों की कुल राशि 37719 करोड़ रुपये रही है।

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ कर 434.60 अरब डालर की रिकार्ड ऊंचाई पर

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान बढ़ कर 434.60 अरब डालर की नयी ऊंचाई पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने को मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा कि एक अक्टूबर को विदेशी विनिमय भंडार ने ऊंचाई का नया रिकार्ड कायम किया। अप्रैल के शुरू से एक अप्रैल की अवधि में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 21.7 अरब डालर की वृद्धि हुई है। केंद्रीय बैंक के ताजा साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह के बाद विदेशी मुद्रा भंडार 5.022 अरब डालर बढ़ कर 433.594 अरब डालर के स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह भंडार 38.8 करोड़ डालर घट कर 428.572 अरब डालर पर आ गया था। सप्ताह के दौरान ज्यादातर वृद्धि विदेशी मुद्रा सम्पत्तियों में बढ़ोतरी से हुई। इस तरह की सम्पत्तियां सप्ताह के दौरान 4.944 अरब डालर बढ़कर 401.615 अरब डालर पर पहुंच गयीं। डालर के मुकाबले अन्य मुद्राओं की विनिमय दरों में घट बढ़ से अन्य मुद्राओं में पड़ी विदेशी मुद्रा सम्पत्तियों का मूल्य भी प्रभावित होता है।

सप्ताह के दौरान रिजर्व बैंक के पास पड़ा स्वर्ण भंडार 10.2 करोड़ डालर बढ़कर 26.945 अरब डालर के बराबर रहा। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के पास भारत का विशेष आहरण अधिकार 70 लाख डालर कम हो कर 1.428 अरब डालर रहा। इसी तरह मुद्राकोष के पास जमा भारत का आरक्षित कोष भी 1.70 करोड़ डालर घट कर 3.606 अरब डालर के बराबर रहा।

50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को दिवाली तोहफा

5 फीसद बढ़ा महंगाई भत्ता

नई दिल्ली। एजेंसी

मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली तोहफा दिया है। सरकार ने बुधवार को महंगाई भत्ते में 5 फीसद का इजाफा करने का फैसला लिया है। इससे 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। यह बढ़ी हुई दरें इस साल जुलाई से ही लागू होंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी दी है कि सरकार ने डीए को 12 फीसद से बढ़ाकर 17 फीसद करने का निर्णय किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुआ है।

केंद्र सरकार के इस निर्णय से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ ही 65 लाख पेंशनर्स को भी फायदा होगा। हालांकि, इस फैसले से सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो बढ़ते राजस्व घाटे के बीच सरकार की सरदर्दी और बढ़ाएगा। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार ने आशा वर्कर्स का मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने एक और अहम फैसला किया है। इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अब 30 नवंबर तक आधार की सीडिंग कराई जा सकती है।

जावड़ेकर के मुताबिक डीए में एक बार में की गई यह सर्वाधिक वृद्धि है। उन्होंने कहा, ''पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक बार में डीए में पांच फीसद का इजाफा किया है।'' केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि महंगाई भत्ता इससे पहले सिर्फ 2-3 फीसद तक ही बढ़ता था, जो कि मोदी सरकार द्वारा अब 5 फीसद बढ़ाने का फैसला हुआ है। मंत्री ने कहा कि यह फैसला दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियां लाएगा। इस साल 27 अक्टूबर को दीपों का त्योहार दिवाली मनाया जाएगा। बता दें कि महंगाई भत्ते में यह बढ़ोत्तरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

मंगोलिया में भारतीय मदद से बन रही रिफाइनरी का निर्माण शुरू होने के साक्षी बने प्रधान

नयी दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगोलिया में भारतीय मदद से बन रही रिफाइनरी के निर्माण कार्य के शुभारंभ पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। आधिकारिक बयान के अनुसार इस रिफाइनरी के निर्माण के लिए भारत ने 1.236 अरब डॉलर की ऋण सहायता दी है। प्रधान अधिकारियों और कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगोलिया की यात्रा पर हैं। यह पिछले महीने मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद का दौरा है। बयान के मुताबिक मंगोलिया के प्रधानमंत्री यूख्नागिन खुरेलसुख, मंगोलिया सरकार के छह मंत्री और डोर्नोगोवी प्रांत के गवर्नर टी. एनख्तुवशिन के साथ प्रधान ने रिफाइनरी का निर्माण शुरू होने पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधान ने कहा, भारत और मंगोलिया के बीच के ऐतिहासिक संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की यात्रा से और मजबूत हुए हैं। पिछले महीने मंगोलिया के राष्ट्रपति बट्टुल्गा खाल्तमा की भारत यात्रा ने इसे और प्रगाढ़ किया।'' इस रिफाइनरी की सालाना उत्पादन क्षमता 15 लाख टन है।

बाजार में भारी बढ़त

सेंसक्स 645 अंक उछला, निफ्टी 11,300 के पार बंद

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बुधवार को शेयर बाजार भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 645.97 अंक बढ़कर 38,177.95 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 186.90 अंक उछलकर 11,313.30 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 हरे निशान और 12 लाल निशान पर बंद हुए। आज सुबह सेंसेक्स 96.07 अंकों की बढ़त के साथ 37,628.05 पर खुला जबकि निफ्टी आज 26.55 अंकों की बढ़त के साथ 11,152.95 पर खुला। सेंसेक्स के जिन शेयरों में तेजी रही उनमें इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और कोटक बैंक के शेयर रहे, जबकि गिरावट वाली शेयरों में यस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, एचसीएलटेक, आईटीसी और टीसीएस के शेयर रहे। वहीं, निफ्टी के शेयरों की बात करें तो इसमें इंडसइंड बैंक, इंफ्राटेल, भारती एयरटेल, एसबीआईएन के शेयर है, वही लूजर शेयरों की बात करें तो यस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन के शेयरों में गिरावट रही।

करदाताओं के लिए ई-असेसमेंट योजना, अधिकारियों के सामने जाने की जरूरत नहीं होगी

नई दिल्ली। एजेंसी

आयकर विभाग ने सोमवार को बिना सीधे संपर्क वाली ई-असेसमेंट योजना की शुरुआत की। इसे कराधान सुधारों की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। इस योजना से करदाताओं को कर अधिकारियों का आमना-सामना की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने यहां राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र (एनईएसी) का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। शुरुआत में राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र के तहत 58,322 आयकर मामलों का चयन किया गया है।

इस योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को करनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के साथ अन्य आधिकारिक व्यस्तताओं की वजह से वह इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाईं। राजस्व सचिव ने कहा कि इस पहल से करदाता के लिए सुगमता और सुविधा बढ़ेगी। इस योजना को रेकॉर्ड समय में शुरू किया गया है।

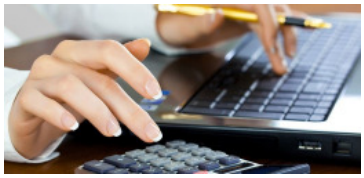

पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी

राजस्व विभाग ने कहा, 'नई पहल से आकलन प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच आमना-सामना की जरूरत नहीं होगी।' राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र देश भर में अधिकारियों के दखल के बिना ई-आकलन योजना में मदद करेगा। इससे करदाताओं को लाभ होगा। राजस्व विभाग ने कहा कि इस योजना से करदाताओं को अनुपालन में आसानी होगी, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, कामकाज में विशेषज्ञता आएगी, आकलन की गुणवत्ता का स्तर सुधरेगा और मामलों का निपटान तेजी से हो सकेगा।

2,686 अधिकारियों को जिम्मेदारी

इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का काम आयकर विभाग के 2,686 अधिकारियों को सौंपा गया है। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में पांडेय ने कहा, 'जिस किसी करदाता का मामला जांच के लिए चुना जाएगा, वह अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा करा सकेगा। इसके अलावा, आकलन करने वाले अधिकारी का चयन भी बिना क्रम के किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे मामलों को जांच के लिए चुना जाएगा, जिनमें गंभीर खामियां मिलेंगी।

बजट में हुई थी योजना की घोषणा

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार व्यक्तिगत आयकर में छूट देने पर विचार कर रही है, राजस्व सचिव ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह योजना शुरू करने की घोषणा की थी। सीतारमण का कहना था कि अभी कर आकलन में करदाता और अधिकारी को आमने-सामने आने की जरूरत होती। इससे कर अधिकारियों द्वारा कुछ 'अवांछित व्यवहार' के मामले भी सामने आते हैं।

GST कम होगा तभी FIT रहेगा इंडिया

इंडस्ट्री को सरकार से बूस्टर का इंतजार

नई दिल्ली। मोदी सरकार फिट इंडिया मूवमेंट के जरिये देश मे खासकर युवाओं को फिट बने रहने का संदेश दे रही है। इससे देश में फिटनेस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिला है। पिछले कुछ समय में दिल्ली मुम्बई जैसे बड़े शहरों में जिम, योगा सेंटर या फिटनेस सेंटर की संख्या तेजी से बढ़ी है। लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री का मानना है कि अगर सरकार फिटनेस इंडस्ट्री को टैक्स खासकर जीएसटी की दरों में थोड़ी रियायत दे तो इससे ना केवल फिटनेस मूवमेंट को और अधिक सफल बनाया जा सकता है, साथ ही मेक इन इंडिया मिशन को भी इससे काफी मदद मिलेगी।

स्पोर्ट्स इक्यूपमेंट पर जीएसटी घटाने की मांग

दरअसल फिटनेस इंडस्ट्री - फिटनेस के लिए ज़रूरी तमाम मशीन या इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, जिम बाइसिकल, रनिंग मशीन, वगरह ज़्यादातर समान चीन से आता है। इसके चलते घरेलू मैन्युफैक्चर्स को काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। फिटनेस इंडस्ट्री के मुताबिक इसके अलावा फिटनेस प्रोडक्ट्स या इक्विपमेंट पर लगने वाले 18इ जीएसटी दर की वजह से चुनौती और बढ़ जाती है।

देश में बन रहे स्पोर्ट्स इक्यूपमेंट

संजय बत्रा, एमडी बेन्सन स्पोर्ट्स (benson sports) के मुताबिक इंडस्ट्री फिटनेस इक्विपमेंट केटेगरी में कई प्रोडक्ट देश मे ही बनाए जा रहे हैं। इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलाह है। सरकार जीएसटी की दरों में कटौती करती है तो एक तरफ जहां फिटनेस मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा वहीं बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

चीन से मिल रही चुनौती

स्वदेश कुमार , प्रोजेक्ट हेड-स्पोर्ट्स इंडिया 8 सालों से दिल्ली में फिटनेस इंडस्ट्री प्लेयर्स को साथ लेकर मेगा शो करते आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों से इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में चीन का दबदबा बढ़ा है. ऐसे में सरकार को भारतीय उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे.

प्रमुख बंदरगाहों पर माल ढुलाई मामूली बढ़कर 34.8 करोड़ टन

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों से माल ढुलाई चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर अवधि में मामूली 1.48 प्रतिशत बढ़कर 34.84 करोड़ टन रही। भारतीय बंदरगाह संघ (आईपीए) के आंकड़ों के मुताबिक, इस बढ़ोतरी की वजह कोकिंग कोल, उर्वरक और लौह अयस्क की ढुलाई में बढ़ोतरी है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में इन बंदरगाहों से माल ढुलाई 34.33 करोड़ टन थी। आईपीए के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के प्रमुख 12 बंदरगाहों से माल ढुलाई अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान 34.84 करोड़ टन रही। ये 12 बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह (पूर्व में कांडला), मुंबई बंदरगाह, जवाहर लाल नेहरू, मुरगांव बंदरगाह, न्यू मंगलौर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह, वी ओ चिदंबरनार बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह (हल्दिया समेत) हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा माल ढुलाई दीनदयाल बंदरगाह पर देखी गई। यहां से 6.10 करोड़ टन माल ढुलाई हुई। इसके बाद, पारदीप (5.55 करोड़ टन), विशाखापत्तनम बंदरगाह (3.47 करोड़ टन), जवाहरलाल नेहरू (3.44 करोड़ टन), हल्दिया समेत कोलकाता बंदरगाह (3.16 करोड़ टन) और मुंबई (3.01 करोड़ टन) का स्थान है। चेन्नई से 2.47 करोड़ टन माल ढुलाई जबकि न्यू मंगलौर बंदरगाह से 1.78 करोड़ टन की माल ढुलाई हुई।अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान, प्रमुख बंदरगाहों से कोकिंग कोल की ढुलाई 15.25 प्रतिशत बढ़कर 2.92 करोड़ टन रही जबकि तापीय कोयले की ढुलाई में 13.20 प्रतिशत की गिरावट आई। तैयार उर्वरक की ढुलाई में 11.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तीन देशों से आयातित कुछ इस्पात उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क जारी रखने की मांग, सरकार करेगी जांच

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से आयातित कुछ हॉट रोल्ड इस्पात उत्पादों पर डंपिंगरोधी शुल्क जारी रखने के संबंध में जांच शुरू कर दी है। जांच के जरिये यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि इन उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क समाप्त होने के बाद भी क्या इनकी डंपिंग जारी रह सकती है। इस बारे में घरेलू उद्योग की ओर से सरकार को शिकायत की गई है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की अधिसूचना के अनुसार जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लि.और जिंदल स्टेनलेस लि. ने संयुक्त रूप से चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से आयातित 'स्टेनलेस स्टील-304 ग्रेड के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद' पर मौजूदा डंपिंग रोधी शुल्क को जारी रखने के लिए आवेदन किया है। भारत ने जून, 2015 में इन उत्पादों पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया था। डीजीटीआर ने अधिसूचना में कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर प्राधिकरण की राय है कि चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद पर डंपिंग रोधी शुल्क जारी करने को लेकर समीक्षा की जरूरत है। यदि जांच से यह स्थापित होता है कि डंपिंग रोधी शुल्क को हटाने से इन उत्पादों की डंपिंग फिर शुरू हो सकती है तो डीजीटीआर इस शुल्क को कुछ और समय तक जारी रखने की सिफारिश करेगा। शुल्क लगाने के बारे में अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय करेगा।

मैंगलोर रिफाइनरी का परिचालन वापस से सामान्यः अधिकारी

मेंगलुरू । मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) में मिट्टी कटाव की वजह से हुईं दिक्कतों को दूर कर लिया गया है और परिचालन सामान्य हो गया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक एम. वेंकटेश ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह में भारी बारिश की वजह से कंपनी के रिफाइनरी परिसर में मिट्टी का कटाव होने लगा था और उससे फेज -3 में एक पाइप रैक पर असर पड़ा था। सुरक्षा के मद्देनदर अगस्त के तीसरे हफ्ते में पूरे फेज - तीन परिसर को बंद कर दिया गया था। पाइप रैक की मरम्मत के बाद रिफाइनरी के फेज -3 परिसर को सितंबर के दूसरे हफ्ते के दौरान फिर से शुरू किया गया है। वेंकटेश ने कहा कि तब से पूरा रिफाइनरी परिसर पूरी क्षमता के साथ सामान्य तरह से काम कर रहा है। हाल ही में सऊदी अरब की

एक रिफाइनरी और तेल क्षेत्र में ड्रोन हमले से एमआरपीएल को होने कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई थी और परिचालन सामान्य रूप से चल रहा था। वेंकटेश ने कहा कि मैंगलोर रिफाइनरी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत क्षेत्र के सामाजिक विकास में योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारा ज्यादा ध्यान दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले पर है। 2019-20 में सीएसआर पर 50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रहे हैं।

पैन-आधार लिंकिंगः 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ी डेडलाइन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्रालय ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी है। यह समयसीमा 30 सितंबर 2019 को खत्म होने वाली थी। शनिवार को ऍऊ की ओर से जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी गई है। सरकार के इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने PAN को आधार से नहीं जोड़ा है। 31 दिसंबर तक PAN को आधार से ना जोड़ने पर यह इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी आप इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

यह सातवीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाई है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अब अनिवार्य हो चुका है। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था।आयकर कानून की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।

PAN 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आधार 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ओर से जारी किया जाता है। आप इसे I-T वेबसाइट या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। PAN को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई अंतर ना हो।

यदि कोई अंतर हो तो यूजर को पहले इसे ठीक कराना होगा। आधार में गलती होने पर UIDAI से और PAN में को बदलाव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कराना होगा। यदि आपका PAN आधार से लिंक नहीं है तो आप तब तक किसी वित्तीय लेनदेन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक इसे आधार से ना जोड़ लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 8.47 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स में से 6.77 करोड़ ने पैन को आधार से लिंक कर लिया है। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है।

ग्रॉसरी स्टोर्स को भी मिल सकती है खांसी और जुकाम की दवा बेचने की मंजूरी

नई दिल्ली। एजेंसी

आपको जल्द ही ग्रॉसरी स्टोर्स पर खांसी, जुकाम या फ्लू जैसी साधारण बीमारियों के लिए दवाएं मिल सकती हैं। स्टैंडर्ड ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (ण्ञ्एण्ध्) नॉन-प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के लिए उपयुक्त साइज वाली 'यूनिट डोज पैकेजिंग' शुरू करने के एक प्रपोजल पर विचार कर रहा है। इससे दवाओं के गलत या अधिक इस्तेमाल की आशंका दूर हो सकेगी। देश में ओवर-द-काउंटर (ध्ऊ) दवाओं पर बनाई गई एक्सपर्ट्स की एक सब-कमिटी ने 'पर्याप्त लेबलिंग' का सुझाव दिया है, जिससे उपभोक्ता दवाओं को खुद चुन सकेंगे। एक्सपर्ट्स ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा सकने वाली दवाओं के लिए अलग पैकेजिंग रखने का सुझाव दिया है।

OTC दवाओं की दो कैटिगरी बनाई जाएंगी

OTC दवाओं के लिए दो अलग कैटिगरी बनाई जाएंगी। इनमें से एक कैटिगरी की दवाएं रिटेल आउटलेट पर बेची जा सकेंगी और दूसरी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के यहां से मिल सकेंगी। लेबलिंग को लेकर सुझावों को अगर मंजूर किया जाता है, तो सभी ध्ऊ दवाओं का जेनेरिक नाम, फॉर्म्युलेशन का ब्रांड नाम, कंपोजिशन, पैक में डोज की संख्या जैसी जानकारी देनी होगी।

फिलहाल OTC दवाओं की कोई परिभाषा नहीं

देश में अभी तक OTC दवाओं की कोई परिभाषा नहीं है। एक्सपर्ट्स की सब कमिटी ने कहा है कि एक दवा को ध्ऊ घोषित करने से पहले फॉर्म्युलेशन की कम से कम चार वर्ष तक बिक्री की जानी चाहिए।

पिछले महीने DCC की बैठक में लिया गया फैसला

पिछले महीने हुई एक ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी (DCC) की मीटिंग में OTC दवाओं को दो कैटिगरी में बांटने का फैसला किया गया था। फिजिशियन, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स अब हर फॉर्म्युलेशन की जांच कर उसे OTC दवा की कैटिगरी में रखने की सिफारिश कर सकेंगे।

दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी

एक अधिकारी ने बताया, 'अभी ऐसी कई दवाएं हैं, जो ध्ऊ या प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कैटिगरी में नहीं आतीं। ऐसी दवाओं की जांच कर उन्हें सही कैटिगरी में रखना चाहिए।' खांसी, जुकाम, फ्लू और गर्भनिरोधक दवाएं ध्ऊ कैटिगरी में आती हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'नए सिस्टम को अगर मंजूरी मिलती है और इसे लागू किया जाता है तो साधारण दवाओं के गलत या अधिक इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी।'

प्रपोजल का इंडस्ट्री ने स्वागत किया

मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन आर सी जुनेजा ने इस प्रपोजल का स्वागत किया है। उनका कहना है, 'अगर इसे बेहतर तरीके से लागू किया जाता है तो यह एक अच्छा कदम होगा। इससे अधिक दवाएं लेने की समस्या समाप्त होगी।' देश में OTC मार्केट 9 पर्सेंट के CAGR से बढ़कर 2026 तक 6.5 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है।

ऐड को लेकर भी निर्देश जारी करने की अपील

एक्सपर्ट्स ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसी दवाएं बनाने वाली कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया से क्लीयरेंस लेने के बाद अपने प्रॉडक्ट्स का विज्ञापन देने की अनुमति होनी चाहिए। अभी ऐसी दवाओं के विज्ञापन की अनुमति नहीं है।

लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बीएसई ने मिलाया फिक्की से हाथ

नयी दिल्ली। एजेंसी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) और स्टार्टअप के माहौल को बढ़ावा देने के लिए बीएसई ने उद्याग मंडल फिक्की के साथ मिलकर सोमवार को एक परिचर्चा सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का मकसद मौजूदा नीतियों में कमियों की पहचान करना और अच्छी नीतियों लिए सुझाव देना है। इसके अलावा एक सत्र का आयोजन एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाली उद्यम साथी और उद्यम सखी जैसी पहलों के प्रसार के लिए भी किया गया। एमएसएमई को इस सत्र में उनके विचार और सुझाव रखने के लिए आमंत्रित किया गया। साथ ही मंत्रालय के स्तर पर उनकी चिंताओं वाले मुद्दों पर भी बातचीत की गयी। बीएसई ने एक बयान में कहा, ''कुछ चिंता वाले मुद्दों की पहचान की गयी है। इसमें एमएसएमई की परिभाषा को सरल बनाना, कोष की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऋणदाताओं के रुख में बदलावा लाना, भुगतान में देरी छीक करन और एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना प्रमुख है।'' इस सत्र में 20 एमएसएमई समेत करीब 40 हितधारकों ने प्रतिभाग किया।

सैमसंग ने चीन में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह बंद किया

सियोल। एजेंसी

अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर की वजह से आर्थिक मोर्चे पर पहले से ही मुसीबतें झेल रहे चीन को कोरियाई दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने जोर का झटका दिया है। सैमसंग ने चीन में स्मार्टफोन का विनिर्माण पूरी तरह से बंद कर दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, कंपनी ने चीन में श्रम की बढ़ती लागत के मद्देनजर यह कदम उठाया है। भारत में अपने संयंत्रों का विस्तार कर रही कंपनी ने शुक्रवार को ई-मेल के जरिये जारी एक बयान में कहा कि उसने चीन में स्थित अपने दूसरे कारखाने में भी स्मार्टफोन का विनिर्माण बंद कर दिया है।

इससे पहले कंपनी ने पिछले साल चीन के तिआनजिन में स्थित एक अन्य कारखाने को बंद किया था। कंपनी ने कहा कि उसने अपने कारखानों की 'दक्षता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है।' वैसे दक्षिण कोरिया के मीडिया ने कहा है कि सैमसंग ने चीन में मोबाइल फोन का विनिर्माण कार्य बंद किया है, उसका एक कारण यह भी है कि वहां मजदूरी खर्च बढ़ गया है।

कंपनियों को लुभाने में लगा भारत

ट्रेड वॉर के कारण मुसीबतें झेल रही चीन में मौजूद वैश्विक कंपनियां पहले से ही विनिर्माण के लिए दूसरे देश में जगह तलाश रही हैं। भारत ने कॉर्पोरेट पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती करके इन कंपनियों को भारत में संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, कंपनियों को लुभाने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार कुछ बड़े इंसेंटिव दे सकती है। इनमें सस्ता कर्ज, प्लांट और मशीनरी के लिए क्रेडिट गारंटी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) 2.0 स्कीम शामिल हैं।

भारत में बढ़ेगी दिलचस्पी

अधिकारियों ने बताया कि इससे ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की दिलचस्पी भारत में प्लांट लगाने में बढ़ सकती है। सरकार ने हाल ही में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15 पर्सेंट के टैक्स रेट की घोषणा की थी। इससे चीन जैसे देशों से कंपनियों को भारत शिफ्ट कराने में मदद मिलेगी।

3 नई स्कीमों के प्रपोजल पर काम

इस साल की शुरुआत में ईएमसी ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तीन नई स्कीमों का प्रपोजल भेजा था। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तीन बड़ी स्कीमें- मॉडिफायड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम (MSIPS), EMC और इलेक्ट्रॉनिक डिवेलपमेंट फंड पिछले साल खत्म हो गई थी। इसके बाद ईएमसी ने नई स्कीमों का प्रपोजल दिया था।

प्रौद्योगिकियों के सम्मिलन से जुड़े नियामक मुद्दों का समाधान जरूरी : सूचना और प्रसारण सचिव

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने बुधवार को कहा कि प्रौद्योगिकियों के सम्मिलन से उत्पन्न होने वाले नियामक मुद्दों का समाधान किए जाने की जरूरत है। उन्होंने 'ओवर दि टॉप' प्लेटफार्म और डिजिटल मीडिया के नियमन के मुद्दे पर सुझाव भी मांगे। 'ओवर दि टॉप' (ओटीटी) प्लेटफार्म उन माध्यमों को कहते हैं जो परंपरागत केबल या सैटेलाइट टीवी के बिना इंटरनेट के जरिए टीवी और फिल्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं। खरे यहां 'प्रसारण में उभरते रुझान' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रेस, फिल्म प्रमाणन और प्रसारण के लिए अलग-अलग नियामक हैं, लेकिन अब ये तीनों प्रौद्योगिकी सिर्फ एक उपकरण में मिल रही हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (इरडा) और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'तो ये चुनौतियां हैं... प्रौद्योगिकी में तेज गति से बदलाव, प्रौद्योगिकी का आपस में मिलन और इन चुनौतियों से उठने वाले नियामक मुद्दे हैं।' उन्होंने ओटीटी प्लेटफार्म और डिजिटल मीडिया के नियमन के मुद्दे पर सुझाव भी मांगे। खरे ने कहा, 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हम इन (प्रौद्योगिकी) बदलावों को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं और हम सभी विचारों का स्वागत करेंगे, खासतौर से ओटीटी और डिजिटल मीडिया की वृद्धि और इसे कैसे नियमित किया जाए, उसके मामले में।'' इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्मों की तरह ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियमन की बात कही थी।

मतदाता सूची को आधार से जोड़ने के चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय कर रहा विचार

नई दिल्ली। कानून मंत्रालय मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं और नए आवेदकों की प्रविष्टियों की जांच के लिए आधार संख्या लेने को वैधानिक समर्थन देने पर विचार कर रहा है।इस बारे में चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है ताकि मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर नहीं रह सके। अगस्त 2015 में आधार कार्ड के संबंध में दिए अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने मतदाता सूची को यूआईडीएआई (आधार) संख्या से जोड़ने की चुनाव आयोग की योजना को रोक दिया था। चुनाव आयोग उस समय राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनईआरपीएपी) के तहत आधार संख्या ले रहा था।

आयोग ने कानून मंत्रालय को लिखे एक पत्र में प्रस्ताव दिया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों में संशोधन किया जाए ताकि चुनाव आयोग मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों और जो पहले से सूची में हैं, उनसे आधार संख्या ले सके. सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्रालय निर्वाचन कानून में संशोधन पर विचार कर रहा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एजेंसी को बताया, 'कार्रवाई की जा रही है.' चुनाव आयोग द्वारा अगस्त में भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि निर्वाचन कानूनों को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि चुनाव पंजीकरण अधिकारी मौजूदा मतदाताओं के साथ ही नए आवेदन करने वालों से उनकी आधार संख्या मांग सकें।

IHS मार्किट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI सितंबर में 51.4 पर रहा, अगस्त में भी इंडेक्स इसी स्तर पर था

नई दिल्ली। देश और विदेश से कमजोर मांग का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है। इससे भारतीय कंपनियों के प्रॉडक्शन और इनवेंटरी में कमी हुई है। उन्होंने इनपुट की खरीदारी भी घटाई है। IHS मार्किट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इश्ष सितंबर में 51.4 पर रहा। इससे पिछले महीने भी इंडेक्स इसी स्तर पर था। यह मई 2017 के बाद इसका सबसे खराब प्रदर्शन है। सर्वे रिपोर्ट से यह भी पता चला कि पिछले महीने में बिजनेस कॉन्फिडेंस ढाई साल के निचले स्तर पर चला गया और कंपनियां खुद को बुरे वक्त के लिए तैयार कर रही हैं। IHS मार्किट की प्रिंसिपल इकनॉमिस्ट और इस रिपोर्ट को लिखने वाली पॉलियाना डी लीमा ने बताया, 'वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ सुस्ती बनी रही।' इस साल जून तिमाही में देश की उअइ ग्रोथ 5 प्रतिशत के साथ 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। अगस्त के कोर सेक्टर डेटा से भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती बने रहने का संकेत मिला था। इस साल सितंबर तिमाही में 2017 की इसी तिमाही के बाद मैन्युफैक्चरिंग PMI का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। हालांकि, इस तिमाही में कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने स्थिति में सुधार के संकेत दिखने की बात कही। इंटरमीडिएट गुड्स कंपनियों के बिजनेस में भी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कैपिटल गुड्स सेगमेंट में कमजोरी बनी हुई है।

रेनो की अगले साल तक भारत से कलपुर्जों का निर्यात दोगुना करने की योजना

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

फ्रांस की कार कंपनी रेनो की भारत से वाहनों के कलपुर्जा निर्यात कारोबार से आमदनी अगले साल तक दोगुना करने की योजना है। कंपनी ने भारत में तैयार कलपुर्जों का अपने विभिन्न वैश्विक परिचालनों को निर्यात कर 2018 में करीब 19 करोड़ यूरो का राजस्व अर्जित किया था। कंपनी की योजना मध्यम अवधि में भारत में वाहन बाजार में हिस्सेदारी दोगुना करने की है। इसके लिये कंपनी 2022 तक एक इलेक्ट्रिक वाहन समेत तीन नये मॉडल पेश करने वाली है। घरेलू यात्री वाहन बाजार में रेनो की हिस्सेदारी करीब चार प्रतिशत है। कंपनी की योजना नये उत्पादों तथा मौजूदा उपभोक्ताओं की मदद के लिये बिक्री एवं सेवा नेटवर्क को दोगुना करने की भी है। रेनो इंडिया के प्रबंध निदेशक वेंकटराम मामिल्लापल्ले ने पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में कहा, ''हम काफी कलपुर्जों का निर्यात करते हैं, करीब 19.80 करोड़ यूरो के कलपुर्जों का वैश्विक स्तर पर सालाना निर्यात किया जा रहा है। इसे अगले साल की पहली छमाही तक दोगुना करने की योजना है।'' उन्होंने कहा कि निर्यात से भारत में कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं को जोड़े रखने में मदद मिल रही है। कंपनी इंजन के हिस्सों तथा प्लास्टिक एवं वाहन की बॉडी के हिस्सों का निर्यात रूस, ब्राजील, रोमानिया, कोलंबिया, अर्जेंटीना और मोरक्को जैसे देशों को करती है। वाहनों के निर्यात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी करीब 10 हजार क्विड का हर साल दक्षिण अफ्रीका निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका और एशिया प्रशांत में ट्राइबर का निर्यात करने की योजना है।

बैंकरों को मार्च तक दरों में 0.25 से 0.40 प्रतिशत और कटौती की उम्मीद

मुंबई। एजेंसी

रिजर्व बैंक की आर्थिक वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुये देश के प्रमुख बैंकरों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान मार्च तक नीतिगत दर में 0.25 से लेकर 0.40 प्रतिशत तक और कटौती की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक न सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि की चिंता में रेपो दर को इस वर्ष में लगातार पांचवीं बार कटौती की है। मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन चली बैठक के बाद शुक्रवार को रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.15 प्रतिशत कर दिया। एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और कार्यकारी उपाध्यक्ष अभीक बरुआ ने कहा की ताजा कटौती हालांकि, उम्मीद के अनुरूप की गई है लेकिन शेयर बाजार में इससे ज्यादा की उम्मीद की जा रही थी।

आर्थिक वृद्धि आंकड़े में कटौती से भी बाजार में निराशा छा गई। स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की ताजा कटौती और इसके साथ ही आगे भी दरों में कटौती को लेकर नीतिगत स्वीकार्यता से यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक सुस्ती को थामने के लिये राजकोषीय और मौद्रिक नीतिगत उपाय दोनों साथ साथ काम करेंगे। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक समीक्षा में आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया। इसके साथ ही केन्द्रीय बैंक ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने पर उसका ध्यान रहेगा। इससे आने वाले दिनों में और कटौती का संकेत मिलता है। स्टैनचार्ट के मुख्य कार्यकारी जरीन दारुवाला ने कहा कि रिजर्व बैंक ने एक बार फिर वृद्धि के लिये अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। उसने ताजा कटौती के साथ ही भविष्य के लिये भी मौद्रिक नीति को उदार बनाये रखने की प्रतिबद्धता जताई है। पंजाब नेशनल बैंक के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि रिजर्व बैंक का नजरिया उदार बना रहेगा, इससे आगे और कटौती की संभावना बनती है।

राव ने कहा कि शुक्रवार को हुई कटौती सरकार द्वारा घोषित राजकोषीय उपायों के लिये सही मायनों में पूरक साबित होगी और इससे निजी खपत और निवेश गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक पदमजा चुंद्रू ने कहा कि मुद्रास्फीति लक्षित दायरे में है और रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख को उदार बनाये रखा है। कोटक महिन्द्रा बैंक के उपभोक्ता बैंकिंग अध्यक्ष शांति एकंबरम ने कहा कि मौजूदा त्यौहारी सत्र मांग और खपत बढ़ने के लिहाज से काफी अहम है। भविष्य में उठाये जाने वाला कोई भी कदम राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों स्तर पर दिये गये लाभ के मांग और वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करेगा। आईबीए के मुख्य कार्यकारी वीजी कण्णन ने कहा कि एक बार फिर रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि को अधिक तवज्जो दी है। केनद्रीय बैंक ने घरेलू वृद्धि को बढ़ाने के सरकार के हाल के उपायों को पूरक समर्थन दिया है।

वैराग्य की प्रतिमूर्ति भगवान राम

श्रीराम ने विजयादशमी के दिन रावण का वध कर मानवता को उसके त्रास से मुक्ति दिलाई। उन्होंने राजा के रूप में अपनी प्रजा का पालन इस तरह किया कि रामराज एक उदाहरण बन गया। किंतु वास्तव में प्रभु श्रीराम का मूल स्वभाव वैरागी का था।

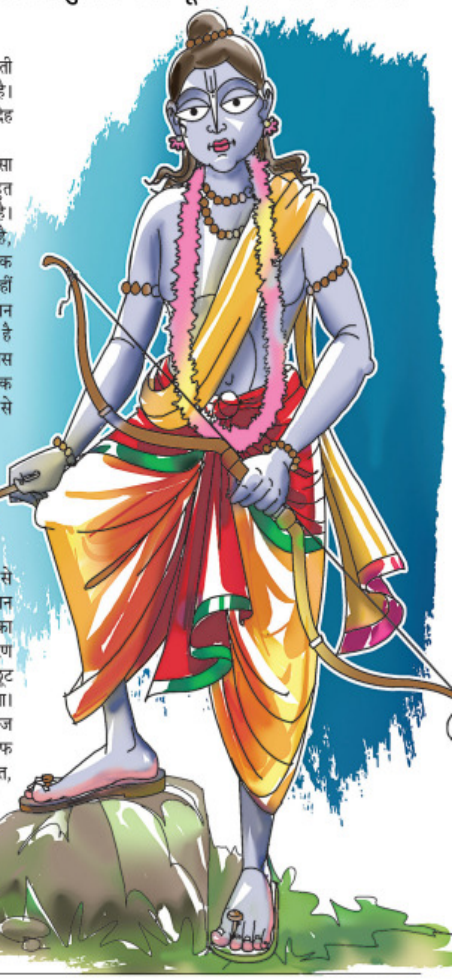

श्रीराम के जन्म की कथा, सीता से विवाह, सीता का हरण, रावण से युद्ध- ये उनके जीवन के कुछ मुख्य पहलू हैं, परंतु श्रीराम के जीवन का एक ऐसा पक्ष भी है, जिसके विषय में अधिकांश लोग कुछ भी नहीं जानते। आइए, आज उनके जीवन के उसी पहलू को जानते हैं।

श्रीराम अपने भाइयों के साथ गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम से विद्याध्ययन समाप्त करने के बाद महल में सुखपूर्वक अपने मां-पिता के साथ रह रहे थे। फिर एक दिन वह अपने पिता से कहते हैं, 'हे परमात्मा तुल्य पिता! मैं आपसे तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा चाहता हूं।' राम की युवा अवस्था है। वह देखने में सुंदर हैं। इस समय तो उनके मन में वासनाएं होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए। पर यहां वह अपने धर्मात्मा पिता दशरथ से तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा ले रहे हैं। राजा दशरथ ने प्रसन्नता से आज्ञा दे दी।

विजयादशमी पर विशेष

आनन्दमूर्ति गुरुमां

यह बात सुन कर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहने लगे कि हम भी साथ जाएंगे। पिता जी से इनको भी आज्ञा मिल गई। ये सारे भाई एक-एक करके चारों दिशाओं में गए। वहां पवित्र नदियों में स्नान करके पर्वतों, कंदराओं, नदियों के तट पर बैठकर जप करते थे। चूंकि राजकुमार हैं, अतः दान भी करते थे। योगीश्वरों, तपीश्वरों, महात्माओं, हठयोगियों का दर्शन करके उनकी विलक्षण जीवनशैली, वैराग्य, तपस्या, अनुशासन, संयम देख-देखकर इनके कोमल चित्त बहुत प्रभावित हुए। चार दिशाओं में सभी नौ खंडों में मौजूद पवित्र तीर्थों का दर्शन करके सब प्रकार से संतुष्ट होकर घर वापस लौट आए।

इनके माता-पिता बहुत प्रसन्न हुए कि राम भाइयों सहित सुरक्षित घर वापस आ गए। पर कुछ दिनों बाद एक अजब परिवर्तन श्रीराम के व्यवहार में दिखने लग गया। अब राम ज्यादा बोलते नहीं हैं, परिवार के सदस्यों के बीच नहीं बैठते, अकेले रहते हैं, भोजन भी नहीं करते। धीरे-धीरे उनका शरीर कमजोर होने लग गया और पिता को चिंता होने लग गई। राजा दशरथ के अनुरोध पर गुरुदेव वशिष्ठ महल में आते हैं।

राम को संदेशा भेजा गया कि गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव का नाम सुनते ही जैसे रोगी शरीर में एक ऊर्जा का संचार हो जाए, ऐसे ही राम की बुझी हुई आंखों में एक रोशनी आ गई। गुरुदेव के समक्ष पहुंच कर साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा, 'राम! ऐसी क्या बात है, जो तुम्हें इतना दुखी कर रही है?' राम ने कहा, 'गुरुदेव! मैं यह देखता हूं कि मनुष्य का मन सदैव कामना से पीड़ित रहता है। बाल्यावस्था में बालक मां-पिता पर आश्रित है। भूख लगे तो बोल नहीं सकता कि भूख लगी है। युवावस्था में मन ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से पीड़ित रहता है। वृद्धावस्था तो दुख रूप है। जैसे दीमक लगा वृक्ष अंदर से समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार कामनाओं का घुन मनुष्य को समाप्त कर देता है। इन कामनाओं से मैं बाहर कैसे आऊं? मानव अपने दुखों के कारणों को इकट्ठा करता रहता है और फिर उन्हीं कारणों से व्यथित होता रहता है। ऐसे जीवन को जीते हुए मैं क्या खुश होऊं? क्या मुस्कुराऊं, क्या प्रसन्नता के गीत गाऊं? मुझे तो शोक हो रहा है। मेरा हृदय संतप्त है। मेरा हृदय पीड़ित है।'

'योग वासिष्ठ' ग्रंथ में श्रीराम और वशिष्ठ जी का यह पूरा संवाद है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि सांस भी क्यों ले रहे हैं? जिस शरीर की नियति मृत्यु है, जिस शरीर की नियति रोग है, जिस शरीर को काल ने एक दिन समाप्त कर देना है, उस देह के साथ ममता कैसे हो सकती है? मूढ़ व्यक्ति ही देह से ममता कर सकता है। जिसके अंदर विवेक जाग्रत हो जाए, वह देह से ममता नहीं कर सकता।

> **चित्त**
> व्यथित हो, तो निवारण ज्ञान से ही हो सकता है। वशिष्ठ जी ने श्रीराम को योग और ज्ञान का उपदेश दिया। यह श्रीराम के आध्यात्मिक जीवन का पक्ष है। यदि मन में श्रीराम के वैराग्य की एक किरण भी आ जाए, तो काम हो जाएगा।

गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने शिष्य में ऐसा वैराग्य देखकर कहा, 'राम! मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू मेरा सबसे प्यारा शिष्य है। मेरे सभी शिष्यों में शिरोमणि तू ही है, क्योंकि ज्ञान मैंने सबको दिया, पर विवेक सबको नहीं हुआ। जिसको विवेक नहीं हुआ, उसको वैराग्य नहीं हो सकता। ज्ञान के फलस्वरूप तुमने विवेक को प्राप्त किया है और उसी विवेक रूपी फूल की खुशबू वैराग्य है, जिस वैराग्य के कारण से तेरे जीवन में यह वीतरागता छलक रही है।' राम की इस भूमिका में वह विवेक और वैराग्य से पुष्ट एक शिष्य हैं।

वशिष्ठ जी श्रीराम को ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर राम के चित्त को विश्राम हुआ और ब्रह्मानुभूति हुई। श्रीराम मानव के रूप में लीला कर रहे हैं, इसलिए अपना स्वरूप भूल गए। अज्ञानता से चित्त व्यथित हो, तो उसका निवारण ज्ञान से ही हो सकता है। वशिष्ठ जी ने श्रीराम को योग और ज्ञान का उपदेश दिया। यह श्रीराम के आध्यात्मिक जीवन का पक्ष है। यदि आपके मन में श्रीराम के वैराग्य की एक किरण भी आ जाए, तो काम हो जाएगा। आप आसक्तियों से छूट जाओगे, व्यर्थ की ममता से बच जाओगे। मन निर्मल होगा। इस निर्मल हुए, इस शुद्ध हुए मन के अंदर ही ज्ञान का बीज डाला जा सकता है। जैसे बर्तन गंदा हो, तो पहले उसे साफ करते हैं, फिर उसमें दूध भरते हैं। इसी तरह से आसक्ति, तृष्णा, क्रोध, ममता से भरे हुए मन में ज्ञान नहीं डाला जा सकता।

चित्त को वैराग्य से शुद्ध करो। वैराग्य विवेक से आयेगा। इस छोटे-से जीवन में वैराग्य और विवेक का फूल खिल जाये तो जीवन कृतार्थ हो जाए।

आस्था स्थली: सोमेश्वरनाथ मंदिर, अरेराज, बिहार

यहां पूरी होती है संतान की कामना

पूर्वी चंपारण स्थित अरेराज का सोमेश्वरनाथ मंदिर बिहार का एक सुप्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहां सालों भर संतान की कामना लिए श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहता है। हर वर्ष, विशेषकर भाद्रपद शुक्लपक्ष चतुर्दशी (जिसे अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है) को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान सोमेश्वर नाथ का जलाभिषेक किया जाता है। यहां का शिवलिंग धरातल से तकरीबन 20 फुट नीचे है। सोमेश्वर नाथ शिव मंदिर का वर्णन स्कंद, पद्म एवं वराह पुराण में भी किया गया है। यह मंदिर काफी पुराना है, लेकिन इसका कोई

लिखित इतिहास अभी तक नहीं मिला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस शिवलिंग की स्थापना चंद्रमा (जिसका एक नाम सोम भी है) ने गौतम ऋषि से मिले श्राप से मुक्ति के लिए की थी। इसलिए इस शिवलिंग को सोमेश्वर नाथ कहा जाता है।

मान्यता है कि गौतम ऋषि का निवास स्थान अरेराज मंदिर से तकरीबन 160 किलोमीटर पूर्व दिशा में मधुबनी जिले के अहिल्या स्थान में था। यहीं देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का सतीत्व छल से भंग किया था, जिसमें चंद्रमा ने इंद्र की सहायता की थी। जब भगवान राम जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने जा रहे थे, तब मुनि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। जहां गौतम ऋषि रहते थे, वहां एक विशाल मंदिर और शिला है। यह स्थान आज अहिल्या स्थान के नाम से मधुबनी जिला में प्रसिद्ध है। धनुष तोड़ कर सीता से विवाह करने के बाद भगवान राम अयोध्या वापस जा रहे थे, तब राम परिवार ने रास्ते में पड़ने वाले अरेराज मंदिर में भगवान सोमेश्वर नाथ की पूजा की थी। अरेराज मंदिर आज भी जनकपुर-अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक पूजनीय तीर्थ-स्थल है, क्योंकि अरेराज अयोध्या से जनकपुर जाने वाले राम-जानकी मार्ग में स्थित है।

एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार, वनवास काल में पांडव कुछ समय तक यहां रुके थे। उस समय द्रौपदी प्रतिदिन बाबा सोमेश्वर नाथ की पूजा करती थीं। तब यह क्षेत्र अरण्यराज के नाम से जाना जाता था। यहां दूर तक चम्पा फूल के वन थे। चम्पा फूल का वन होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम आज भी चम्पारण है, जो पूर्वी चम्पारण और पश्चिम चम्पारण के नाम से दो जिलों में विभाजित है। शिवहर जिला के अदौरी स्थित बागमती और लालबकैया नदी के संगम से लाखों की संख्या में शिवभक्त कांवर में जल भर कर 96 किलोमीटर नंगे पांव चल कर भगवान सोमेश्वर नाथ को जलार्पण करते हैं। उल्लेखनीय है कि श्रद्धालु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को जल लेते हैं और सड़क पर नंगे पांव चल कर त्रयोदशी की शाम को अरेराज मंदिर में जलार्पण करते हैं। उसके बाद चतुर्दशी को पूरा दिन उपवास रखकर सबेरे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। फिर वहां से दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित भैरव बाबा को जल चढ़ाते हैं। गौरतलब है कि जहां सोमेश्वरनाथ का लिंग 20 फीट गहराई में है, वहीं भैरव बाबा का लिंग 25-30 फीट ऊपर एक विशालकाय टीले पर स्थित है। भैरव स्थान पर मंत्र साधना भी होती है।

कामना लिंग के नाम से प्रसिद्ध सोमेश्वरनाथ मंदिर में बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश एवं नेपाल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहां लग्न के समय प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में विवाह एवं जनेऊ संस्कार होते हैं। यहां ठहरने के लिए धर्मशाला एवं होटल की सुविधा उपलब्ध हैं।

कैसे पहुंचें: यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन मोतिहारी है, जहां से अरेराज मंदिर की दूरी 30 किलोमीटर है। यहां का नजदीकी हवाई अड्डा पटना है। अरेराज से पटना 146 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से बस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।

बजरंगबली सिंह

शरद पूर्णिमा (13 अक्तूबर) पर विशेष

रास में गोपी बन गए महादेव

जब अमृत बरसाने वाली शरद पूर्णिमा को भगवान श्रीकृष्ण ने वृन्दावन में रासलीला का आयोजन किया, तो उसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित रखा गया था। उस महारास में एकमात्र पुरुष भगवान श्रीकृष्ण थे। महादेव के मन में रासलीला देखने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसमें शामिल होने के लिए वे गोपिका का रूप धारण कर वृन्दावन पहुंच गए और श्रीकृष्ण की लीला का आनंद लिया।

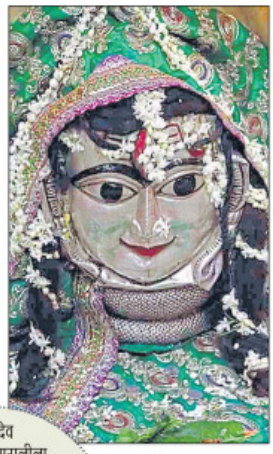

महारास की रात्रि शरद पूर्णिमा की महिमा का वर्णन प्राचीन धर्मग्रंथों में विभिन्न रूपों में किया गया है। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन से सर्दियों का आरम्भ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं के साथ उदित होकर अमृत की वर्षा करते हैं। खीर बना कर शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखना चाहिए और सुबह भगवान को भोग लगाकर सभी को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि चांद से बरसा अमृत औषधि का काम करता है। इससे मानसिक और दमा जैसे रोग नष्ट हो जाते हैं।

> महादेव के मन में रासलीला देखने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसमें शामिल होने के लिए वे गोपी रूप धारण कर वृन्दावन पहुंच गए और रासलीला का आनंद लिया। शरद पूर्णिमा की महिमा का वर्णन प्राचीन धर्मग्रंथों में विभिन्न रूपों में किया गया है।

जगत कल्याण के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने महारासलीला शरद पूर्णिमा के दिन ही की थी। इस दिन संतान की कामना के लिए महिलाएं कोजागरी व्रत रखती हैं। इसके अलावा मां लक्ष्मी, राधाकृष्ण, शिव-पार्वती और कार्तिकेय की पूजा करने का विधान है। देवी भागवत पुराण के अनुसार, मां लक्ष्मी शरद पूर्णिमा की रात्रि यह देखने के लिए पृथ्वी पर विचरण करती हैं कि उस दिन कौन-कौन जागकर उनकी पूजा करता है। उसे मां लक्ष्मी धन-वैभव का आशीर्वाद देती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर 108 बार 'ऊं श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा' मंत्र की आहुति खीर से करनी चाहिए। रात में 100 या इससे ज्यादा दीपक जलाकर बाग- बगीचे, तुलसी और घर-आंगन में रखने चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन देश के कई तीर्थ स्थलों पर लाखों की संख्या मे श्रद्धालु खीर का सेवन करते हैं।

बिहारी लाल तिवारी

गुजरात, मुंबई समेत देश के कई शहरों में एक दिन में हुई 200 मर्सेडीज की डिलिवरी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

ऐसा कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी है और बिक्री में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन इस त्योहारी सेल पर लग्जरी कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी मर्सेडीज बेंज ने मुंबई, गुजरात और देश के अन्य शहरों में एक ही दिन में 200 से अधिक कारों की डिलिवरी की है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसने दशहरा और नवरात्र पर बुक की गई विभिन्न मॉडल की 200 से अधिक कारों की डिलिवरी एक ही दिन में की है।

कंपनी ने बताया कि दशहरा पर अकेले मुंबई में 125 से अधिक कारों की डिलिवरी की गई है जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। वहीं गुजरात में उसने 74 कारों की डिलिवरी नवरात्र पर की है। कंपनी के भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्टिन श्वेंक ने कहा कि दशहरा और नवरात्र में मुंबई और गुजरात के ग्राहकों की ओर से हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। ऐसी ही प्रतिक्रिया हमें 2018 में भी मिली थी। कंपनी ने सी और ई क्लास सेडान के साथ उथ्य और उर्ई जैसे एसयूवी वाहनों की डिलिवरी की है।

हर हफ्ते बिकती है एक लेम्बोर्गिनी

पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक इटली की सुपरस्पोर्ट्स कार कंपनी लेम्बोर्गिनी की बिक्री में इस साल 30 फीसदी के करीब इजाफा हो सकता है। माना जा रहा है कि 2019 में कंपनी 65 यूनिट से ज्यादा की बिक्री कर सकती है। इस लिहाज से हर हफ्ते में एक लेम्बोर्गिनी बिक रही है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ के आसपास है।

2018 में बिकी थी 48 लेम्बोर्गिनी

लेम्बोर्गिनी इंडिया के हेड शरद अग्रवाल ने इकनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा था कि 2018 में कंपनी 48 कार बेची थी। उनका मानना है कि अगले साल (2020) में भी दहाई अंकों की ग्रोथ बनी रहेगी और अगले तीन सालों में कंपनी एक साल में 100 यूनिट कार बेचेगी।

बिक्री में 30-40 फीसदी की गिरावट

दूसरी तरफ, ऑटो सेक्टर की दूसरी कंपनियों का हाल बुरा है। पिछले कुछ महीने में बिक्री में 30-40 फीसदी तक गिरावट आई है। डीलरशिप पर स्टॉक का बोझ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों डीलरशिप बंद हो चुके हैं। बिक्री घटने की वजह से मारुति, ह्यूंदै, होंडा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों ने कई बार प्रॉडक्शन को कई दिनों के लिए रोका है। हेवी व्हीकल बनाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड ने इसी महीने अलग-अलग प्रॉडक्शन सेंटर पर 2-15 दिनों तक काम बंद करने की घोषणा की थी।

इस साल अब तक बिकी एकमात्र नैनो कार

यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस साल (2019) केवल एकमात्र लखटकिया कार नैनो बिकी है। कंपनी ने एकमात्र कार फरवरी महीने में बेची थी। पिछले करीब 9 महीने से इस कार का प्रॉडक्शन भी बंद है। जब कार बिक ही नहीं रही है तो कंपनी प्रॉडक्शन क्यों करेगी। हालांकि, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि BS-VI लागू होने के बाद यह कार किसी भी पैमाने पर खड़ा नहीं उतरती है। ऐसे में चाहकर भी खरीदार इसे नहीं खरीदना चाहेंगे। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, यह संभव है कि फरवरी 2020 के बाद इसका प्रॉडक्शन हमेशा के लिए बंद करने की आधिकारिक घोषणा कर दे।

वालमार्ट ने भारत से झींगे की निर्यात खेप की ब्लाकचेन प्रौद्योगिकी से निगरानी शुरू की

नई दिल्ली। खुदरा स्टोर श्रृंखला चलाने वाली वैश्विक कंपनी वॉलमार्ट ने आंध्र प्रदेश से अमेरिका भेजे जाने वाले समुद्री झींगे की खेप की शुरू से आखिरी ठिकाने तक निगरानी के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि अभी यह परियोजना परीक्षण के रूप में शुरू की गयी है और यह 'भारत के झींगा किसान से विदेशी खुदरा प्रतिष्ठान तक झींगे की खेप पर निगाह रखने के लिए ब्लॉकचेन का पहला ज्ञात उपयोग है।' कंपनी का दावा है कि इससे भारत से समुद्री खाद्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारतीय झींगे की खेप में विदेशी ग्राहकों का विश्वास मजबूत होगा। वॉलमार्ट इंक ने 2017 से ग्लोबल फूड ट्रैसेबिलिटी (खाद्य उत्पादों की खेप की निगरानी) बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग पर आईबीएम के साथ सहयोग किया है। भारत से निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में झींगे का बड़ा योगदान है और इस मामले में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है। विज्ञप्ति के अनुसार, 2018 में भारत ने मूल्य के हिसाब से 46 प्रतिशत झींगा अमेरिका को निर्यात किया। आंध्र प्रदेश झींगे के लिए एक प्रमुख केंद्र है और राज्य सरकार किसानों को अमेरिकी खाद्य मानकों के अनुसार काम करने को प्रोत्साहित कर रही है। विज्ञप्ति में अमेरिका के मत्सय उद्योग संस्थान 'नेशनल फिशरीज इंस्टीट्यूट' के अध्यक्ष जॉन कॉनली के हवाले से कहा गया है, 'ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में समुद्री खाद्य उत्पाद समुदाय को बदलने की संभावना मौजूद है। दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों में शामिल समुद्री खाद्य की एक जटिल और व्यापक आपूर्ति श्रृंखला है और इसमें परीक्षण तथा आपूर्ति श्रृंखला की अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली महत्वपूर्ण है।'

जल्द बिना हॉलमार्क के गहने बिकना होंगे बंद, प्रस्ताव मंजूर

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने सोने के आभूषणों के लिए बीआईएस हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी जल्द बिना हॉलमार्क के गहने बिकना बंद हो जाएंगे। हालांकि अब इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को सूचित करने के बाद ही लागू किया जा सकता है।

डब्ल्यूटीओ के तय नियमों के अनुसार, इस मामले में पहले उसको सूचित करना होगा। इस प्रक्रिया में लगभग दो महीने का समय लग सकता है। गौरतलब है कि गोल्ड हॉलमार्किंग शुद्धता का प्रमाण है और वर्तमान में इसे स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। आगे इसे अनिवार्य बनाया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास हॉलमार्किंग के लिए प्रशासनिक अधिकार है। इसने तीन ग्रेड - 14 कैरट, 18 कैरट और 22 कैरट के सोने के लिए हॉलमार्किंग के लिए मानक तय किए हैं।

बातचीत में उन्होंने बताया कि वाणिज्य विभाग ने एक अक्टूबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे लागू करने के पहले डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में कुछ तकनीकी समस्या है। इसका निपटान जल्द कर लिया जाएगा। मौजूदा समय में, देश भर में लगभग 800 हॉलमार्किंग केंद्र हैं और केवल 40 प्रतिशत आभूषणों की हॉलमार्किंग की जाती है। भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक देश है, जो मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करता है। भारत प्रति वर्ष 700-800 टन सोने का आयात करता है।

क्या है हॉलमार्किंग?

बीआईएस हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने का एक सिस्टम होता है। इससे यह प्रमाणित होता है गहना भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। इसलिए, सोने खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि उसमें बीआईएस हॉलमार्क है।

ऐसे चेक करें हॉलमार्क

यह देखना भी जरूरी होता है कि हॉलमार्क असली है या नहीं? असली हॉलमार्क पर भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोना निशान होता है और उस पर हॉलमार्किंग सेंटर के लोगो के साथ सोने की शुद्धता भी लिखी होती है। इसके अलावा, उसमें जूलरी तैयार करने का साल और उत्पादक का लोगो भी अंकित होता है।

बीएमडब्ल्यू की एम5 कम्पटीशन भारत में पेश, कीमत 1.55 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू ने अपनी प्रीमियम सेडान एम5 कम्पटीशन का उन्नत संस्करण सोमवार को पेश किया। शोरूम में इसकी कीमत 1.55 करोड़ रुपये है। कंपनी ने बयान में कहा कि नई एम 5 कम्पटीशन में 8 सिलेंडर पेट्रोल पावरट्रेन (इंजन) दिया गया है। यह मॉडल सोमवार से सभी बीएमडब्ल्यू डीलरशिप पर उपलब्ध होगा। एम 5 कम्पटीशन आठ स्पीड ट्रांसमिशन के साथ 625 हॉर्स पावर (एचपी) के इंजन के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 किमी की रफ्तार सिर्फ 3.3 सेकंड में पकड़ सकती है। इसके अलावा इस मॉडल में डायनमिक स्टैबिलिटी कंट्रोल , कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल , डायनमिक ब्रेक कंट्रोल समेत अन्य फीचर्स दिए गए हैं।

IMF प्रमुख ने कहा

भारत में आर्थिक मंदी का असर गंभीर, भविष्य को लेकर दी चेतावनी

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की नयी प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएव का कहना है कि वैसे तो इस वक्त समूचे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में हैं, लेकिन भारत जैसी सबसे बड़ी उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में इस साल इसका असर ज़्यादा नज़र आ रहा है। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के तौर अपने पहले संबोधन में उन्होंने यह बात कही। जॉर्जिएव ने संकेत दिया कि चौतरफा फैली मंदी का अर्थ है कि वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि दर इस दशक की शुरुआत से अब तक के निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगी उनके के मुताबिक, दुनिया का 90 फीसदी हिस्सा कम वृद्धि का सामना करेगा. उन्होंने कहा, अमेरिका और जर्मनी में बेरोज़गारी ऐतिहासिक नीचाई पर है... फिर भी अमेरिका, जापान तथा विशेष रूप से यूरोप क्षेत्र की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों में नरमी देखी गई है... लेकिन भारत और ब्राजील जैसी कुछ सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में इस साल मंदी का असर ज्यादा साफ नज़र आ रहा है।

इसी माह क्रिस्टीन लागार्डे के स्थान पर आईएमएफ का शीर्ष पद संभालने वाली क्रिस्टालिना जॉर्जिएव ने कहा कि मुद्राएं एक बार फिर अहम हो गई हैं, और विवाद कई-कई देशों तथा अन्य अहम मुद्दों तक फैल गए हैं। उन्होंने ट्रेड वार में शामिल देशों से बातचीत के जरिए हल निकालने की अपील की है, क्योंकि इसका असर वैश्विक है और इससे कोई अछूता नहीं रह सकता है।

आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। अनुमानित विकास दर में 0.30 फीसदी की कटौती की गई है। आईएमएफ ने विकास दर का अनुमान अब 7 फीसदी कर दिया है। जानकारों के मुताबिक, ऐसा घरेलू मांगों में आई कमी की वजह से किया गया है।

आबीआई ने घटाया विकास दर का अनुमान

वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में भारत की विकास दर पांच फीसदी पर पहुंच गई थी। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस वित्त वर्ष के लिए विकास की दर का अनुमान 6.9 फीसदी से घटाकर 6.1 फीसदी कर दिया है। घटते ग्रोथ रेट पर लगाम लगाने के लिए सरकार और सेंट्रल बैंक की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वैश्विक सुस्ती से भारत कैसे अछूता रह सकता है।

अगले बजट के लिए 14 अक्टूबर से ही काम शुरू करेगी सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्रालय 2020-21 के सालाना बजट की तैयारी प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय को अन्य बातों के अलावा आर्थिक वृद्धि में नरमी और राजस्व संग्रह में कमी के महत्वपूर्ण मसलों का समाधान करना है। यह नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दूसरा बजट होगा।

नवंबर में बैठकों का सिलसिला होगा खत्म

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की बजट इकाई के बजट सर्कुलर (2020-21) के अनुसार, 'बजट पूर्व / संशोधित अनुमान को लेकर बैठक 14 अक्टूबर 2019 से शुरू होगी।' व्यय सचिव की अन्य सचिवों और वित्तीय सलाहकारों के साथ चर्चा पूरी होने के बाद वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों को अस्थाई तौर पर अंतिम रूप दिया जाएगा। बजट पूर्व बैठकें 14 अक्टूबर से शुरू होगी और नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी।

2017 में पहली बार एक फरवरी को बजट पेश किया गया था

वित्त वर्ष 2020-21 का बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने फरवरी के अंत में पेश होने वाले बजट की वर्षों से चले आ रही परंपरा को समाप्त किया है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पहली बार 2018-19 का बजट एक फरवरी 2017 को पेश किया था।

टैक्स संबंधी योजना बनाने में मिलती है मदद

बजट पहले पेश होने से मंत्रालयों को बजट राशि वित्त वर्ष की शुरूआत से आबंटित की जाती है। इससे सरकारी विभाग बेहतर तरीके से व्यय की योजना बना पाते हैं और कंपनियों को व्यापार और टैक्स संबंधी योजना बनाने में मदद मिलती है। पूर्व में जब बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था तब तीन चरणों में संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया मई के मध्य में पूरी हो पाती थी। इससे राशि आबंटित होते-होते मानसून आ जाता। इससे सरकारी विभाग अगस्त के अंत या सितंबर से ही परियोजनाओं पर खर्च शुरू कर पाते।

कच्छ में 1,400 करोड़ रुपये की हवाई अड्डा परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिली

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में वाणिज्यिक हवाई अड्डा विकसित करने के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 1,400 करोड़ रुपये का निवेश होगा। एक आधिकारिक दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विशेषज्ञों की समिति के रुख पर विचार करने के बाद हाल में परियोजना को मंजूरी दी है। मुंदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना को विकसित कर रही है। दस्तावेज में कहा गया कि कुछ शर्तों के साथ मुंदरा इंटरनेशनल हवाई अड्डे की प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दी गई है। कंपनी को सुरक्षा और परियोजना सुविधाओं के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से मंजूरी लेने के लिए कहा गया है। इस परियोजना से 8,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलने का अनुमान है।

रिजर्व बैंक ने राज्यस्तरीय बैंकरों से डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने को कहा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राज्यस्तरीय बैंकर समितियों को पायलट आधार पर एक जिले का चयन करने को कहा है ताकि डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार किया जा सके। रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के लिए सभी राज्यों- संघ शासित प्रदेशों की की बैंकर समितियों (एसएलबीसी-यूएलबीसी) से अपने राज्य में पायलट आधार पर कम से कम एक जिले की पहचान करने को कहा गया है। इन जिलों का चयन बैंकों और अंशधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद किया जपएगा। राज्यस्तरीय

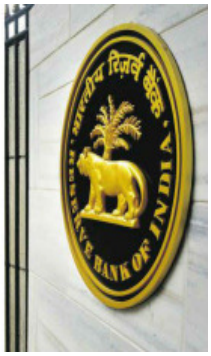

बैंकर समिति का गठन अप्रैल, 1977 में एक शीर्ष अंतर संस्थागत मंच के रूप में सभी राज्यों में उचित संयोजन मशीनरी के सृजन के लिए किया गया था। रिजर्व बैंक ने कहा,"प्रत्येक पहचाने गए जिले को एक बैंक को आवंटित किया जाएगा। उस बैंक को जिले को एक साल में 100 प्रतिशत डिजिटल अनुकूल बनाना होगा। इससे जिले का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित तरीके, तेजी, सस्ती दर और सुविधाजनक तरीके से भुगतान प्राप्त कर सकेगा।"

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।